7 राज्य • 1 केंद्रशासित प्रदेश • 20 संस्करण

# अमर उजाला

• राजधानी वर्ष 16 । अंक 225 । पृष्ठ : 20+16 । मूल्य : चार रुपये नई दिल्ली | शुक्रवार, 23 नवंबर 2018

कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं

तोहफा करतारपुर साहिब दर्शन के लिए केंद्र बनाएगा विशेष कॉरिडोर दिल्ली-एनसीआर



# एयरपोर्ट : भूमि अधिग्रहण के लिए 12.60 अरब मंजूर

## नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के मुताबिक, एयरपोर्ट निर्माण के लिए 8 गांवों की 1441 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा

अमर उजाला ब्यूरो

**लखनऊ।** नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड (जेवर) एयरपोर्ट निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 12 अरब 59 करोड़ 97 लाख 87 हजार 640 रुपये मंजूर किए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जेवर एयरपोर्ट पर हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण के लिए बृहस्पतिवार को सात अरब रूपये जारी भी कर दिए।

नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट निर्माण के लिए 8 राजस्व गांवों की 1441 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इनमें से 1328 हेक्टेयर भूमि तीन हजार भू स्वामियों की है। भूमि अर्जन के लिए 12 अरब 59 करोड़ 97 लाख 87 हजार 640 रुपये का बजट मंजूर किया है। इसमें से सात अरब रुपये नोएडा के कलेक्टर को उपलब्ध क रा दिए हैं। नंदी ने बताया कि इस राशि का उपयोग केवल भूमि अर्जन के लिए किया जाएगा। कलेक्टर को समयबद्ध भूमि अर्जन करने और परियोजना लागत में टाइम ओवर रन हो इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के लिए जल्द ही जमीन का अधिग्रहण शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार का प्रयास है कि जल्द एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का संचालन होगा। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट प्रदेश के पर्यटन, व्यापारिक, औद्योगिक विकास में मिल का पत्थर साबित होगा।

विभाग के प्रमुख सचिव एसपी गोयल ने बताया कि जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना अक्टूबर में जारी की गई थी। कलेक्टर को भूमि का अर्जन कर रिपोर्ट विभाग के निदेशक सूर्यपाल गंगवार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

निविदा और समझौता प्रपत्र तैयार कर शासन को सौंप दिए गए हैं। अब नियाल व पीएमआईसी की बैठक में इसे रखा जाएगा।

-डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ, नियाल

### दिसंबर के पहले सप्ताह में निकलेंगे टेंडर

**ग्रेटर नोएडा।** नोएडा एयरपोर्ट निर्माण के लिए दिसंबर के पहले सप्ताह में टेंडर निकाले जा सकते हैं। निविदा और समझौता प्रपत्र तैयार कर यमुना प्राधिकरण ने शासन को सौंप दिया हैं। शासन के परीक्षण के बाद इसे पीएमआईसी (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इंप्लिमेंट कमेटी) और नियाल (नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड) की बैठक में रखा जाएगा। दोनों बैठक 26 नवंबर को लखनऊ में होगी। यमुना प्राधिकरण ने निर्माण कंपनी के साथ होने वाले समझौते का मसौदा तैयार कर लिया है। यह सलाहकार कंपनी पीडब्ल्यूसी से बनवाया गया है। नीति आयोग द्वारा तैयार मॉडल को इसमें आधार बनाया गया है। ताकि किसी तरह की कमी नहीं रह जाए। दोनों प्रपत्र तैयार कर पिछले सप्ताह शासन को सौंप दिए गए हैं। अब सरकार इनका विधिक व वित्तीय परीक्षण कराएगी। बैठक में मुख्य सचिव, तीनों प्राधिकरणों के सीईओ, सभी प्रमुख सचिव भी मौजूद होंगे। पीएमआईसी से पास होने के बाद इसे नियाल की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद प्रदेश सरकार इसे केंद्र को भेजेगी। इसके बाद ग्लोबल टेंडर (वैश्विक निविदा) निकाल दी जाएगी। ब्यूरो